बिहार सरकार
<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक–प्र07–कम्प्यूटराईजेशन(द्वि0च0)–07/2018– 5268 /खाद्य, पटना/दिनांक– 11.11.19

प्रेषक,

अनिमेष कुमार पराशर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– **जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत PoS यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न/किरासन तेल उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–845 दिनांक 19.02.2018, 2659 दिनांक 18.06.2019, 3152 दिनांक 15.07.2019 एवं भारत सरकार का पत्रांक–1-9/2018-PD.II दिनांक 08.11.2018 एवं 5(3)/2017-PD.III दिनांक 01.02.2018**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य के सभी जिलों में End to End Computerization के द्वितीय चरण में FPS Automation योजनान्तर्गत PoS यंत्रों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। उक्त के आलोक में अब तक 15 जिलों के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में PoS यंत्रों का अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। शेष सभी जिलों में शीघ्र ही PoS यंत्रों का अधिष्ठापन किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में PoS यंत्रों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण हेतु भारत सरकार से प्राप्त निदेशों को अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत् निदेश दिया जाता है :–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में खाद्यान्न प्राप्ति हेतु सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा लाभुकों के पहचान हेतु जीवमित्तीय (बायोमेट्रिक अथवा अन्य दस्तावेज) को उपलब्ध कराने से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश भेजा गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के आलोक में वैसे आच्छादित परिवार जिनके किसी भी परिवार के सदस्यों का आधार सीडिंग नही कराया गया है, को e-KYC के माध्यम से आधार सीडिंग कराने की व्यवस्था PoS यंत्र के माध्यम से की जायेगी। यदि योग्य पात्र लाभुक अब तक आधार इनरौलमेंट तथा आधार सीडिंग से वंचित हैं, उन्हें भी PoS यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। **साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि किसी भी पात्र लाभुक को आधार के एवज में खाद्यान्न से वंचित नही किया जाय एवं छुटे हुए लाभुकों का हर–हाल में PoS यंत्र के माध्यम से आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित की जाय, ताकि अगले माह से सभी पात्र लाभुक सुगमतापूर्वक खाद्यान्न का उठाव कर सके।**

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वैसे लाभुक जिनका उम्र 65 वर्ष से अधिक हो एवं उनके परिवार में कोई 16 से 65 वर्ष तक का कोई वयस्क व्यक्ति न हो एवं वे खाद्यान्न लेने हेतु जन वितरण प्रणाली दुकान तक जाने में असमर्थ हैं, उन्हें भारत सरकार के पत्रांक 5(3)/2017-PD.III दिनांक 01.02.2018 के आलोक में नोमिनी को प्राधिकृत करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

3. पूर्व में विभागीय पत्रांक– 845 दिनांक 19.02.2018 एवं 2659 दिनांक 18.06.2019 द्वारा विभाग/जिला/अनुमंडल/प्रखंड/जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं प्रणाली समाकलक के निर्धारित दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध जवाबदेही तय करते हुए विधि–सम्मत् कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,
11/11
सरकार के अपर सचिव।

अनु0–यथोक्त।

D:\M_2019\Sec_7\Letter_Avim.doc

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन(द्वि0च0)–07/2018– 5268 /खाद्य, पटना/दिनांक– 11.11.19
प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन(द्वि0च0)–07/2018– 5268 /खाद्य, पटना/दिनांक– 11.11.19
प्रतिलिपि – श्री गुरू प्रसाद, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, हैदराबाद, तेलंगना/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना/Linkwell Telysystems Pvt. Ltd, Hyderabad, Telangana को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

(10)

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन(द्वि0च0)–07 / 2018 3152 खाद्य, पटना / दिनांक 15/07/19

प्रेषक,

संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
बिहार।

विषयः– जन वितरण प्रणाली अंतर्गत PoS Machine के माध्यम से खाद्यान्न / किरासन तेल उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 2659 दिनांक 18.06.2019 एवं भारत सरकार का पत्र सं0–5(3) / 2017–PD-III दिनांक 01.02.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं भारत सरकार के निदेशानुसार तथा प्रासंगिक पत्र के आलोक में ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य के सभी जिलों में PoS Machine अधिष्ठापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। PoS Machine के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निदेश को शत प्रतिशत अनुपालन किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में खाद्यान्न प्राप्ति हेतु सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा लाभुकों के पहचान हेतु जीवमितीय (बायोमेट्रिक) अथवा अन्य दस्तावेज को उपलब्ध कराने से संबंधित दिशा निदेश भेजा गया है। (छायाप्रति संलग्न) उक्त के आलोक में वैसे आच्छादित परिवार जिनके किसी भी परिवार के सदस्यों का आधार सीडिंग नहीं कराया गया है, को E-kyc के माध्यम से आधार सीडिंग कराने की व्यवस्था PoS Machine के माध्यम से की जा रही है परन्तु, जो लाभुक अबतक आधार इनरॉलमेन्ट तथा आधार सीडिंग से वंचित है उनको भी राशन PoS Machine के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में ससमय खाद्यान्न / किरासन तेल का वितरण PoS Machine के माध्यम से सभी लाभुकों को सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0– यथोक्त।

ह0/-
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन (द्वि0च0)–07 / 2018–3152 खाद्य, पटना / दिनांक– 15/07/19

प्रतिलिपि –सचिव, सूचना प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, बेल्ट्रॉन भवन, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना / राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि0, बिहार / सहायक महानिदेशक, UIDAI, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / Linkwell Telesystems Pvt. Ltd, Hyderabad, Telangana को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन (द्वि0च0)–07 / 2018–3152 खाद्य, पटना / दिनांक– 15/07/19

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन (द्वि0च0)–07 / 2018– 3152 खाद्य, पटना / दिनांक– 15/07/19

प्रतिलिपि – सभी उप निदेशक (खाद्य) / अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी पणन पदाधिकारी / सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
विशेष कार्य पदाधिकारी।

199

File No.5 (3)/2017-PD-III
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Food and Public Distribution
*****

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 1st Feb, 2018

To
The Principal Secretary/Secretary,
Food and Civil Supply Department,
[All States/UTs]

Subject: Ensuring supply of foodgrains through PDS to every eligible beneficiary.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and inform that several reform measures have been undertaken to bring about greater efficiency and transparency in the functioning of Public Distribution System since the inception of National Food Security Act, 2013. The main objective of the reform measures has been to ensure assured regular supply of the foodgrains to all the beneficiaries as per their entitlement under the Act in a smooth and hassle-free manner.

2. However, some media reports appearing recently, suggest that some of the beneficiaries experience difficulty in getting their entitled quantum of subsidized foodgrains because of their inability to visit the Fair Price Shop for reasons such as old age, physical disability etc.

3. The matter of distribution of entitled quantity of foodgrains to such beneficiaries has been under the consideration of Government of India. After careful examination of the matter, it is proposed to put in place the **following special dispensation for such beneficiaries**:

(a) NFSA beneficiary(ies), who are above sixty five years of age, or who are differently-abled, and have no other adult family member (16 to 65 years) listed in the Ration card, and are not in a position to visit the Fair Price Shop themselves, would be **eligible to be covered under the special dispensation**.

(b) State/UT Government may consider adopting any of the two approaches mentioned below to ensure regular supply of foodgrains to beneficiaries under such special dispensation:

(i) Home delivery of the entitled quota of foodgrains: State may devise the procedure for supply of foodgrains at the doorstep of such beneficiaries without adding any additional cost to the beneficiaries. A few states like Odisha have adopted this mode for distribution of foodgrains.

(98)

(ii) **Delivery through authorized nominees of such beneficiaries:** Such beneficiaries should apply for special dispensation to the authority issuing ration cards along with details and Aadhaar number of their nominee for receiving the entitled foodgrains on their behalf. Such nominee must fulfill following conditions:

- The nominee must be a NFSA beneficiary tagged to the same FPS.
- Foodgrains should be issued to the nominee only after proper authentication/ identification as in case of any other NFSA beneficiary.
- FPS dealer or his/her family members cannot be authorized as a nominee.

(iii) After approval, the nominee may be added in the ration card of such beneficiary and would be entitled to receive the ration of such beneficiary on his/her behalf.

(iv) Vigilance Committee(s) may also be advised to identify and recommend such beneficiaries to be covered under special dispensation to the concerned District Supply Officer.

4. State/UT Governments may consider adopting the above mentioned special dispensation with modification, if any, to ensure timely supply of foodgrains under NFSA to such identified beneficiaries.

Yours faithfully,

(D.K. Gupta)
Director (PD)
Tel: - 23070429

(97)

F.No.1-9/2018-PD.II (E.358148)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

*****

Krishi Bhawan, New Delhi – 110001
Dated the 08th November, 2018

To

Principal Secretary/Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
All States/UTs

Subject: Requirement of Aadhaar as per verdict of Hon'ble Supreme Court of India – reg.

References:

1. **Aadhaar notification SO No. 371(E) dated 08.02.2017 and as extended from time to time.**
2. **Advisory to States/UTs for Aadhaar seeding with ration cards vide letter number 1(8)/2017-PD-II dated 24.10.2017**

Sir/Madam,

I am directed to refer to notification issued by this Department vide SO No. 371(E) dated 08.02.2017 under Section-7 of the Aadhaar Act for use of Aadhaar in PDS and to inform that Hon'ble Supreme Court of India, in its recent order dated 26/09/2018 in connection with Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012 & connected matters, has held that it is compulsory to possess an Aadhaar number (or proof of making an application for enrolment where Aadhaar number is not assigned) for those who seek to receive any subsidy, benefit or service under the welfare schemes of the Government, expenditure whereof is to be met from the Consolidated Fund of India. An added requirement is that such individual would be required to undergo biometric authentication (fingerprint/IRIS) at the time of receiving such benefit/subsidy, etc.

2. It is further informed that the aforesaid notification issued under Section-7 was extended from time to time, and has been last extended up to 31.12.2018 vide notification SO No. 4998(E) dated 27.09.2018. In view of that, it is necessary that the available time up to 31.12.2018 is utilized to allow beneficiaries who do not possess an Aadhaar number to obtain the same by making an application to the Competent Authority. To achieve this State/UT Governments may organize special drives/camps at different locations in the State (with special focus on rural/remote areas). As per first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 of the notification dated 08/02/2017, all State/UT Governments are requested to ensure that till the time an Aadhaar number is assigned to a beneficiary, such beneficiary shall not be

Scanned by CamScanner

denied subsidized foodgrains or cash transfer of food subsidy on the ground of non possession of Aadhaar. In such cases, the benefit (subsidized foodgrains/cash transfer) shall be allowed upon producing either Aadhaar Enrolment ID slip or a copy of application submitted for obtaining an Aadhaar number, along with valid ration card and any of the 8 documents as specified in the said Notification.

3. The Hon'ble Supreme Court has also directed that failure of authentication should not automatically result in the denial of subsidy/benefit/service to any genuine beneficiary; instead, alternate methods should be adopted for identifying such persons, after finding the causes of failure in their cases. Also if biometric authentication through fingerprint of a person fails due to change/deformation of fingerprints (old age beneficiaries); or due to damage to the fingers as a result of accident or some disease etc. or due to some kind of disability, and authentication through IRIS also fails due to certain reasons including blindness of a person, in such situation a suitable provision shall be made for establishing identity of such persons by alternate means.

4. This Department has already provided for such an arrangement vide letter dated 24.10.2017 (copy enclosed) wherein, in case of failure of biometric authentication due to network/connectivity/linking issue or due to poor biometric of the beneficiary or other technical reasons, the beneficiary is to be provided subsidized foodgrains or cash transfer of food subsidy on the basis of physical production of Aadhaar card by him/her in place of biometric authentication, as provided by Section 7 of Aadhaar Act ["proof of possession of Aadhaar number"], along with ration card. In all cases where Aadhaar based online authentication is not feasible and the benefit, service or subsidy is provided on the basis of exception handling mechanism as described in para-6 of the letter dated 24.10.2017, the transactions shall be duly recorded in exception handling register as prescribed in the said letter and these may be audited from time to time. It is further re-iterated that no beneficiary should be denied subsidized foodgrains under NFSA only on grounds of failure of biometric authentication for reasons stated above.

5. All State/UT Governments are therefore requested to initiate necessary actions, as may be required, on above points urgently.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(D.K. Gupta)
Director (PD)
Tel: 23070429

Scanned by CamScanner